

रायपुर को स्मार्ट सिटी अवॉर्ड, और बेहतर बनाने जुटेंगे

आयुक्त रजत बंसल ने दिल्ली में लिया इनाम, बोले- अभी स्मार्ट नहीं हुआ है शहर, लगेगा समय

रायपुर। निप्र

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को तेज संस्थागत कार्य के लिए 21 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बीडब्ल्यू (बिजनेस कर्ल) स्मार्ट सिटी अवॉर्ड दिया गया। आयुक्त और स्मार्ट सिटी सीईओ रजत बंसल ने यह अवॉर्ड हासिल किया। इस कैटेगरी में जयपुर, भुवनेश्वर और नागपुर को भी अवॉर्ड मिले। केंद्र सरकार ने रायपुर स्मार्ट सिटी की घोषणा 24 मई, 2016 को की थी, 17 अगस्त को स्पेशल पर्स कीकल (एसपीवी) का गठन किया गया था।

अवॉर्ड पर सीआईओ बंसल ने बताया कि 16 सितंबर को कंपनी एकट के तहत एसपीवी का पंजीयन कराया। एसपीवी गठन और पंजीयन के बाद रायपुर स्मार्ट सिटी

9 फर्मों से ली गई है निविदा
जल्दी होंगी नियुक्तियां



निगम आयुक्त रजत बंसल

लिमिटेड ने तेजी से काम किया, स्मार्ट सिटी के प्रमुखों के क्रियान्वयन के लिए पीएम से नियुक्ति के लिए आरएफपी जारी कर 9 फर्मों से निविदा ली गई

एरिया बेर्स डिवेलपमेंट (एबीडी) प्रोजेक्ट

प्राथमिकता में मोतीबाग का फर्स्ट फेज डिवेलपमेंट, शास्त्री बाजार को हाईजेनिक मार्केट बनाना यहां बायो कम्पोस्ट प्लांट लगाना, आनंद समाज वाचनालय का कायाकल्प, इंडोर स्टेडियम में वार्किंग ट्रैक, जारिंग के लिए ग्रीन कारीडोर के टेंडर लग चुके हैं। जवाहर बाजार व्यावसायिक परिसर में सह पार्किंग निर्माण होगा।

है। जिनकी जल्द नियुक्तियां होगी। आयुक्त ने इस दौरान यह भी दोहराया कि यह सफलता है, लेकिन रायपुर स्मार्ट नहीं हुआ है। अभी बहुत काम करना है।

पांच प्रोजेक्ट, जिनसे शहर आधुनिक होगा

- **मोतीबाग-** मोतीबाग में हार्ट बाजार, फूड कोर्ट के साथ साइट डिवेलपमेंट के गुरुवार को टेंडर जारी कर दिए। यह काम 87 लाख रुपए से होगा। इसके पहले 2 टेंडर लगे थे। इस साल मोतीबाग आकार ले लेगा।
- **इंटेलीज़ैंट ट्रैफिक सिस्टम-** शहर में ई-रिक्षा चलेंगे। इसके लिए निगम 3 विकल्पों पर सोच रही है, जिसमें रिक्षा के बदले ई-रिक्षा देने पर प्रमुखता से विचार चल रहा है। इतना ही नहीं, 8-9 साल पुराने ऑटो बैन होंगे। इसके लिए चिनिंहंकन होगा। इसके साथ-साथ ट्रैफिक सेंस डिवेलप करने अभियान भी चलेगा।
- **बस स्टॉपेज का ग्लोबल टेंडर-** बस स्टॉपेज जर्जर पड़े हुए हैं। लंबे समय से शहर में बस स्टॉपेज विवाद चल रहा है, मामला हाईकोर्ट में है। अब आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि इस पर ग्लोबल टेंडर जल्द जारी करें।